

Serious long-standing problems of weavers of Nathnagar, Bhagalpur

1159. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether he is aware of the serious long-standing problems of the poor weavers of Nathnagar, Bhagalpur; and

(b) if so, the action taken by Government to redress their long-standing problems?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI): (a) Yes, Sir.

(b) The main problem of the weavers of Nathnagar, Bhagalpur, is the fluctuations in yarn prices; especially of staple yarn and also marketing of finished goods. The State Government has taken up an Export Project at Bhagalpur. Bihar State Handloom Development Corporation has opened a yarn depot at Bhagalpur for supply of yarn to weavers. This will ease the problems of weavers to some extent.

वर्ष 1976-77 में बन्द पटसन मिलें

1160. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1976-77 में कितने पटसन मिल बन्द पड़े रहे और उनके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई; और

(ख) क्या सरकार का इन बन्द मिलों को पुनः खोल कर स्थिति में सुधार करने का विचार है और यदि हाँ, तो किस तारीख से ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा माईति): (क) पटसन वर्ष 1976-77

के अन्त तक सात पटसन मिलें बन्द रही जिसके फलस्वरूप 48.59 लाख श्रमिक दिवस और लगभग 60,000 मी० टन उत्पादन की हानि हुई।

(ख) इन में से चार मिलों में उत्पादन शुरू हो चुका है, शेष में से एक को मशीनों के गत प्रयोग होने और उत्पाद-मिश्र के असन्तुलित होने के कारण पुनः चालू करने योग्य नहीं समझा गया है और अन्य दो मिलों के बारे में सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार कर रही है।

Requirements of enriched Uranium and Heavy Water for Tarapur Power Plant

1161. DR. VASANT KUMAR PANDIT:

SHRI YASHWANT BOROLE:

Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) what are the total requirements of enriched Uranium and heavy water for the full functioning of the Tarapur Power Plant;

(b) how much of the supplies of Nuclear Fuel is expected from U.S.A. or some other country; and

(c) whether it is a fact that Government are considering improvising heavy water and specialised Nuclear Fuel in India, if so, the steps taken thereon and the results expected?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) About 17 to 21 tonnes of enriched uranium are required annually for Tarapur Atomic Power Station (TAPS). No heavy water is needed for its operation.

(b) For the time being we are expecting a supply of 7.6 tonnes from U.S.A.

(c) Technical studies on use of alternative fuels are in progress. As heavy water is not required for functioning of Tarapur Station, the question of finding alternatives does not arise.

मंत्रालय के जे०सी०बी० विभाग के तृतीय श्रेणियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

1162. श्री महीलाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के ज्वाइंट साइफर ब्यूरो, विभाग में तृतीय श्रेणी के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए वर्ष 1970 से विभागीय पदोन्नति समिति की कोई बैठक नहीं हुई है जिसके कारण कर्मचारियों की पदोन्नतियां रूकी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न बुलाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाये बिना द्वितीय श्रेणी के अराजपत्रित कर्मचारियों की तदर्थ आधार पर पदोन्नति की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है और ऐसा भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) और (ख). ग्रुप 'ग' के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के आधार पर भरने के लिए जब कमी नियमित पद खाली हुए तो उन पर विचार करने के लिए 1970 के बाद विभागीय पदोन्नतन समिति की बैठकें हुई हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) नौ अफसरों को पदोन्नत किया गया है । ग्रुप 'ख' (राजपत्रित) के उच्चतर पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया जा रहा है । इस बारे में अंतिम निर्णय हो जाने तक और ज्वाइंट साइफर ब्यूरो में काम करने की दक्षता बनाये रखने के लिए ग्रुप 'ख' के अराजपत्रित कर्मचारियों का वर्तमान नियमों के अधीन तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है ।

Additional Funds for National Highways

1163. SHRI SARAT KAR: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Orissa Government have requested the Central Government for additional funds for National Highways which are under consideration; and

(b) if so, what is the amount sanctioned by the Central Government against the State Government's requirement?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) and (b). The State Government asked for increasing the allocation for National Highway (Original) Works from Rs. 270 lakhs to Rs. 322.57 lakhs. Within the available resources and keeping in view the overall requirements for development, works of all National Highways in all the States and the necessary priorities, the original allocation for Orissa has since been increased to Rs. 300 lakhs.

As regards Maintenance and Repairs, the State Govt's demand is Rs. 144 lakhs. However, keeping in view the availability of resources and the assessed requirements of various National Highways in all States, a sum of Rs. 94.01 lakhs has been released for Orissa.